सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-30 अंक-12 22 जून, 2015 पृष्ठों की संख्या 8 मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती मूल्य : 2 रुपये

घोटालेबाज ललित मोदी के लिए यात्रा दस्तावेज जुटाने में सुषमा स्वराज के घोर गैरकानूनी व अनैतिक कार्य की एसयूसीआई(सी) ने की कड़ी निन्दा

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से उनके तुरंत इस्तिफे की मांग

एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉ. प्रभाष घोष ने 16 जून का निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया:

केन्द्रीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के इस घृणित कार्य की हम कड़ी निन्दा करते हैं जिसमें उन्होंने अपनी अधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग करते हुए यूके सरकार के साथ मध्यस्थता कर घोर गैरकानूनी तरीके से आईपीएल के पूर्व चेयरमैन, धनशोधन(मनी लांड्रिंग) के अभियुक्त और केन्द्रीय जांच एजेन्सी प्रवर्तन निदेशालय से भागे हुए ललित मोदी की खातिर यात्रा दस्तावेज मुहैया कराने का बंदोबस्त किया। इसने एक बार फिर खुलासा कर दिया है कि एक साफ-सुथरा भ्रष्टाचारमुक्त समाज देने का आरएसएस-बीजेपी गठजोड़ का दावा कितना खोखला और कपटभरा था। इसके विपरीत, इसने यह भी खुलासा कर दिया है कि कैसे श्रीमती सुषमा स्वराज जैसे बुर्जुआ शासक जब चाहें, तब नीति-नैतिकता के उच्च सिद्धांतों को पैरों तले रौंद रहे हैं जो एक देश में सरकार चलाने के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं।

हम मांग करते हैं कि श्रीमती सुषमा स्वराज को मंत्रिमण्डल से तुरंत इस्तिफा दे देना चाहिए और केन्द्रीय सरकार को मामले की जांच करने और उचित कार्यसाधकता के साथ सच्चाई उजागर करने के लिए एक उच्च स्तरीय न्यायायिक कमेटी गठित करनी चाहिए।

रेलवे के निजीकरण के कदम का एसयूसीआई द्वारा कड़ा प्रतिवाद

इसे रोकने के लिए जोरदार आन्दोलन का आह्वान

एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 15 जून को जारी एक बयान में कहा :

यह बड़े आक्रोश का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ अति घनिष्ट उनके प्रिय पात्र के रूप में जाने जाने वाले एक बुर्जुआ अर्थशास्त्री श्री विवेक देवराय की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने शासक पूंजीपति वर्ग की इच्छा पूर्ति में भारतीय रेल का निजीकरण करने के लिए तुरंत कठोर कदम उठाये जाने की बेशर्मी से सिफारिश की है। अब तक भारतीय रेल का स्तर दर स्तर निजीकरण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के रास्ते और इसी तरह के दूसरे तरीकों से लोगों को अंधेरे में रख कर छिपे तौर पर किया जा रहा था। लेकिन अब पर्दा उठ गया है और रेल संचालन को निजी पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने के बीजेपी सरकार के मनहूस एजेण्डे को इसी मकसद से गठित आज्ञाकारी कमेटी से वांछित सिफारिश करवा कर अंजाम दिया जा रहा है। भारत के आम लोगों के खून-पसीने से निर्मित भारतीय रेल दुनिया की बड़ी-बड़ी रेलवें में से एक है और सार्वजनिक धन से पैदा एक राष्ट्रीय सम्पत्ति है। जाहिर है कि इस प्रमुख राष्ट्रीय सम्पत्ति को निजी पूंजीपतियों को सौंपने की न तो इजाजत दी जा सकती और न ही यह किसी कीमत पर देश के लोगों को मंजूर है।

इसलिए इस विनाशकारी कदम को देशव्यापी जोरदार आन्दोलन गठित कर नाकाम करना फौरी और निहायत जरूरी है। इसलिए भारतीय रेल के निजीकरण को रोकने के लिए हम देशवासियों को आगे आने और तत्परता के साथ आन्दोलन गठित करने का आह्वान करते हैं। तमाम ट्रेड यूनियनों से भी हमारी पुरजोर अपील है कि जुझारू मजदूर आन्दोलन छेड़ें और आन्दोलन के दबाव से सरकार को यह नितांत जनविरोधी फैसला पलटने को मजबूर कर दें।

महान क्रांतिकारी नेताजी की याद को भुलाने की साजिश को नाकाम करें

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) केन्द्रीय कमेटी का आह्वान

मित्रो,

नेताजी ने एक दिन कहा था, *''करोड़ों भारतवासियों के हक में खड़े होकर उनकी मुक्ति की राह पर खुद को कुर्बान कर जाऊंगा। अगर सत्य की कोई कीमत है, तो मेरे देशवासी समझेंगे मेरे दिल की बात।''* (अग्नियुग) इस बार भी 23 जनवरी करीब-करीब खामोशी में गुजर गयी। क्या इस देश के लोग सचमुच उनके दिल की बात को समझ पाये हैं, सच्चाई की कीमत चुका पाये हैं? गुलाम भारत में 23 जनवरी जज्बात, आदर और प्यार के साथ काफी हलचल पैदा करती थी, कितने ही तरुण सुभाषचन्द्र बनने का सपना देखते थे। और आज आजाद भारत में कितने लोग उन्हें याद करते हैं? देश में ऐसा ही 'विकास' हुआ है! नेताजी ने उस दिन कहा था, *''हमारा यह संघर्ष सिर्फ अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ ही नहीं है, विश्व साम्राज्यवाद के खिलाफ भी है।''* (क्रॉसरोड्स) आज उसी देश के शासक पूंजीवादी नेता गदगद होकर मानवता के घोर दुश्मन लाखों लोगों के हत्यारे अमेरिकी साम्राज्यवाद के राष्ट्रपति का स्वागत कर रहे हैं। नेताजी समेत उस जमाने के क्रांतिकारियों की यादें उन दिनों की तरह आज भी इन शासकों के लिए खतरा हैं। इसलिए नेताजी की यादों को भुला देने की साजिश चल रही है। पाखण्डपूर्ण ढंग से जैसे-तैसे नाममात्र के कुछ आयोजन किये गए, अत्यंत व्यस्त बुर्जुआ मीडिया में भी नेताजी को कोई जगह नहीं मिली।

हृदयविदारक होते हुए भी यह बात सच है कि शासक बुर्जुआ वर्ग और सत्तासीन पार्टियों की साजिश के चलत ही उस जमाने के महान मनीषियों और क्रांतिकारी योद्धाओं की गौरवमय याद आज लगभग विस्मृति के गर्त में खो चुकी है। सिर्फ हमारी पार्टी ही नहीं भूल पायी है। हमारे महान शिक्षक, सर्वहारा मुक्ति-संघर्ष के पथप्रदर्शक कॉमरेड शिवदास घोष ने भूलने नहीं दिया। उन्होंने यह परिस्थिति देखकर गहरी व्यथा-वेदना के साथ कहा था, *''हम छिन्नमूल हो गये हैं! संस्कृति का जो उच्च आधार स्वाधीनता आन्दोलन में तैयार हुआ था, उसकी धारावाहिकता की हम रक्षा नहीं कर पाये। ...देश की सरजमीन पर उभरी उच्च संस्कृति के सुर के साथ हम मानो योग-सूत्र खो बैठे हैं। यदि हम इससे योग-सूत्र ही खो बैठे ... तो हम आज के समय की क्रांति में शरीक कैसे हो सकेंगे? समाज को बदलेंगे कैसे? उस सम्बन्ध को दोबारा कायम करना होगा।''* (शरत् मूल्यांकन के प्रसंग में) उनकी इस सीख से अनुप्राणित होकर ही योग-सूत्र को कायम करने के लक्ष्य के साथ हम हर साल नवजागरण के मनीषियों और नेताजी सहित महान क्रांतिकारियों व शहीदों के स्मृति दिवसों को यथोचित मर्यादा के साथ मनाते हैं ताकि उनके जीवन-संघर्ष और चरित्र-साधना से सीख लेकर हम युगोपयोगी उन्नत चरित्र हासिल कर सकें। इस बार भी हमने देश भर में कई हजार कार्यक्रम किये हैं और पहले की तरह ही बुर्जुआ मीडिया ने उनका कोई कवरेज नहीं दिया है।

आजादी आंदोलन में नेताजी की क्या भूमिका थी, उनके साथ दक्षिणपंथी कांग्रेस नेतृत्व का किन-किन बिन्दुओं पर मतभेद था, किस तरह से साजिश रचकर उन्हें कांग्रेस से निलम्बित और अंततः बहिष्कृत किया गया, इतिहास में अलिखित इन अध्यायों को आज कितने लोग जानते हैं? मृत्यु शैय्या पर लेटे उस जमाने के सिर्फ मुट्ठीभर वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी गहरी पीड़ा के साथ याद करते हैं। देश के इस घोर संकट के दौर में इस विस्मृत अध्याय के कुछ अंशों को याद करना जरूरी है।

नेताजी की सटीक भूमिका का विश्लेषण कर मार्क्सवादी चिंतक कॉमरेड शिवदास घोष ने कहा था, *''...आजादी आंदोलन के दौर में ...हम दो परस्पर विरोधी धाराएं पाते हैं, एक वह जो साम्राज्यवाद और सामंतवाद के साथ समझौतापरस्त रही, समूचे आंदोलन पर यही धारा हावी (Dominant) थी। दूसरी थी, साम्राज्यवाद व सामंतवाद के खिलाफ गैर समझौतावादी धारा। ...गांधीजी समझौतापरस्त सुधारवादी राष्ट्रीय बुर्जुआ के प्रवक्ता थे। इसके विपरीत मध्यमवर्गीय पेटी बुर्जुआ और आम जनता के हिमायती गैर समझौतवादी क्रांतिकारी धारा के सशक्त प्रतिनिधि थे नेताजी सुभाषचंद्र बोस।''* (भारत का सांस्कृतिक आंदोलन और हमारा कर्तव्य) उनकी इस गैर समझौतावादी भूमिका की वजह से ही देश भर की जनता के, खासकर छात्र-युवा शक्ति के दिल पर उन्होंने जीत हासिल की थी। तरूणों की इस शक्ति के प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में एलान किया, 1) कांग्रेस का पहला लक्ष्य है देश की पूर्ण स्वतंत्रता। अगला

(शेष पृष्ठ 2 पर)

महान क्रांतिकारी नेताजी...

(पृष्ठ 1 का शेष)

लक्ष्य है समाजवाद की स्थापना, 2) मजदूरों और किसानों को आजादी की लड़ाई में शामिल करवाना होगा, 3) जमींदारी प्रथा का खात्मा करना होगा। उन्होंने मंच से एलान किया, *''जब पूरी दुनिया साम्राज्यवादियों की साजिश के शिकंजे में है, तो डटा है अकेला समाजवादी सोवियत संघ– जिसका अस्तित्व मात्र ही साम्राज्यवादियों का दिल दहला देता है।''* (क्रॉसरोड्स) अब तक कांग्रेस के घोषणापत्र में ये बातें नहीं थीं। नतीजतन अंग्रेजी साम्राज्यवाद, भारतीय पूंजीवाद और गांधीवादी नेतृत्व आर्तकित हो उठा। तभी उन्होंने जघन्य साजिश रचना शुरू किया ताकि नेताजी अगली बार अध्यक्ष न बन सकें। खुद गांधीजी ने नेताजी के खिलाफ पट्टाभि सीतारमैया को उम्मीदवार बनाया, नेहरू–पटेल उनके पक्ष में प्रचार में उतर गये और पूंजीपतियों ने रुपये दिये। उनके द्वारा संचालित मीडिया ने सीमारमैया के पक्ष में प्रचार किया। बावजूद इसके अंततः नेताजी की जीत हुई। इस तरह से परास्त होकर गांधीवादियों ने नेताजी को मिट्टी का माधो बनाने के लिए घोर साजिश रचना शुरू किया। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधीवादी गोविन्द बल्लभ पंत ने पंत प्रस्ताव लाया। इस प्रस्ताव में था कि अध्यक्ष के तौर पर नेताजी गांधीजी की बगैर अनुमति के न कोई फैसला ले पायेंगे और न ही कार्यकारिणी का गठन (उनके पहले के अध्यक्ष किया करते थे) कर पायेंगे। संयुक्त सीपीआई (जिसका हिस्सा सीपीआई(एम) है) और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (सीएसपी) द्वारा सुभाष चन्द्र बोस के पक्ष में वोट न दिये जाने की वजह से बुर्जुआ वर्ग की यह साजिश कामयाब हो गयी। इस संबंध में नेताजी ने काफी दुख के साथ कहा था, *''त्रिपुरी में मुझे शिकस्त मिली। यह हार थी रोग शैय्या पर पड़े एक व्यक्ति की, जिसे टक्कर दे रहे थे बारह धुरंधर कांग्रेसी नेता, सात राज्यों के कांग्रेसी मंत्री और इनसे भी बढ़कर गांधीजी जैसे एक नेता का नाम, व्यक्तित्व व साख। इसके अलावा इसके साथ जुड़ गयी थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की दगाबाजी। उनका साथ दिया था कम्युनिस्ट पार्टी ने।''* (क्रॉसरोड्स) इसके बाद दक्षिणपंथी कांग्रेस नेतृत्व ने नेताजी को कोई काम नहीं करने दिया। नेताजी ने गांधीजी से हस्तक्षेप करने की गुजारिश की। लेकिन वे खामोश रहे, मानो उन्हें कुछ पता ही न हो। इस स्थिति में मजबूर होकर 1939 में नेताजी ने कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन बुलाकर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ दिनों बाद नेताजी द्वारा अंग्रेज–विरोधी आंदोलन का आह्वान करने पर अनुशासन तोड़ने के आरोप में कांग्रेस आलाकमान ने नेताजी को कांग्रेस से निलम्बित कर दिया, जिसे नेताजी ने व्यवहारतः बहिष्कार कहा। जब रवीन्द्रनाथ ने गांधीजी को हस्तक्षेप करने को कहा, तो उन्होंने नेताजी को 'अनुशासनहीन' कहा। इस तरह से साम्राज्यवादियों के सहयोग से राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व को पूरी तरह से राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग के नियंत्रण में लाया गया। शायद ऐसा नहीं होता, यदि उन दिनों की संयुक्त सीपीआई सशक्त रूप से नेताजी के पक्ष में खड़ी होती। हालांकि आजादी आंदोलन में भारत के कम्युनिस्टों के कर्तव्य का निर्धारण कर महान स्तालिन ने 1925 में कहा था, *''भारत जैसे उपनिवेशों की बुनियादी खासियत है कि वहां का राष्ट्रीय बुर्जुआ समझौतापरस्त है ...ये समझौतापरस्त बुर्जुआ वर्ग साम्राज्यवाद से सांठ–गांठ किए हुए है। बुर्जुआ वर्ग का सबसे रईस व प्रभावकारी तबका देश से भी ज्यादा अपनी तिजोरियों को लेकर फिक्रमंद है और साम्राज्यवाद से ज्यादा डर उसे क्रांति से है ...वे पूरी तरह क्रांति–विरोधी खेमे में जा रहे हैं। वे अपने ही देश के साम्राज्यवादियों से मिलकर मजदूर–किसानों के खिलाफ मोर्चा तैयार कर रहे हैं। इस मोर्चे को ध्वस्त किये बगैर क्रांति को अंजाम नहीं दिया जा सकता ...चूंकि इन देशों में एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी ही सर्वहारा को नेतृत्व दे सकती है, इसलिए अगुआ कम्युनिस्टों का मुख्य नारा होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का स्वतंत्र अस्तित्व। कम्युनिस्ट पार्टी समझौतापरस्त राष्ट्रीय बुर्जुआ को अलग–थलग कर साम्राज्यवाद–विरोधी संघर्ष में शहर और देहात के पेटी बुर्जुआ जनसाधारण को नेतृत्व देने के लिए निश्चित तौर पर क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के साथ खुला मोर्चा तैयार करेगी।''* (रचनावली, खंड–7) संयुक्त सीपीआई ने बिल्कुल उलट काम करते हुए समझौतापरस्त बुर्जुआ वर्ग की ही मदद की। इतना ही नहीं, कांग्रेस से बहिष्कृत होकर नेताजी ने देश के वामपंथियों को एकजुट करने के लिए संयुक्त बिहार के रामगढ़ में एक सम्मेलन का आह्वान किया और सीपीआई सहित तमाम वामपंथियों को शामिल होने का आह्वान करते हुए जब कहा, ''...एकमात्र इसी तरीके से दक्षिणपंथियों के हमलों को रोका जा सकता है और एक मार्क्सवादी पार्टी के निर्माण की जमीन तैयार हो सकती है।'' (क्रॉसरोड्स) तब भी संयुक्त सीपीआई उसमें शामिल नहीं हुई।

एक सशक्त राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता के तौर पर नेताजी मार्क्सवाद और सोवियत समाजवाद को कितनी आदर व आस्था की नजरों से देखते थे, उसका पता उनके कुछ मूल्यवान कथनों से चलता है। उन्होंने कहा था, *''उन्नीसवीं शताब्दी में जर्मनी ने मार्क्सवादी दर्शन के जरिये उल्लेखनीय तौर पर दुनिया की सभ्यता की तरक्की में मदद की थी बीसवीं शताब्दी में रूस ने सर्वहारा क्रांति, सर्वहारा वर्ग के राज्य और सर्वहारा संस्कृति के मामले में कामयाबी हासिल करने के जरिये दुनिया की संस्कृति और सभ्यता को समृद्ध किया है।''* (क्रॉसरोड्स) विश्व कम्युनिज्म की विजय यात्रा के संबंध में कितनी उम्मीद के साथ उन्होंने कहा था, *''दुनिया के मौजूदा हालात में स्रोतों और प्रतिस्रोतों को दो मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है यानी साम्राज्यवादी ताकतों की विपरीत धारा में चल रही साम्यवाद की ताकतें। इसलिए हिटलरवाद के खात्मे का मतलब है साम्यवाद की स्थापना।''* (क्रॉसरोड्स) 1930 में एक और क्रांतिकारी वारीन्द्र घोष को लिखे पत्र में नेताजी ने यहां तक कहा था कि, *''इतने सालों से हम स्वतंत्रता को मात्र राजनैतिक स्वतंत्रता समझते थे। लेकिन अब हमें इस बात का एलान करना होगा कि हम जनता को सिर्फ राजनैतिक गुलामी से ही मुक्त नहीं करायेंगे, बल्कि हम उसे हर तरह की गुलामी से मुक्त करायेंगे। स्वतंत्रता संग्राम का लक्ष्य होगा राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक–तीनों तरह के जुल्मों से मुक्ति। जब हर तरह की गुलामी का खात्मा हो जायेगा, तब कम्युनिज्म के आधार पर नये समाज की स्थापना होगी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य लक्ष्य होगा वर्गविहीन आजाद समाज की स्थापना।''* (लोकमत) इटली के प्रसंग में उन्होंने अफसोस करते हुए कहा था, *''1922 में इटली समाजवाद के लिए हर पहलू से पूरी तरह से तैयार था, उसे जरूरत थी एक लेनिन की। लेकिन ऐसे एक व्यक्ति की गैर मौजूदगी के चलते समाजवादियों के हाथ से यह मौका निकल गया। ...अंततः इटली में समाजवाद की जगह पर फासीवाद स्थापित हुआ।''* (क्रॉसरोड्स) युद्ध में परास्त होकर सुभाषचन्द्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से अपने भाषण में कहा था, *''आज यदि ऐसी कोई एकमात्र हस्ती है, जिसके द्वारा आने वाले कई दशकों के लिए यूरोपीय राष्ट्रों का भाग्य निर्धारित होता है, तो वह हैं मार्शल स्तालिन। इसलिए भविष्य में सोवियत संघ क्या करेगा, इसे जानने के लिए सारी दुनिया और खासकर सारा यूरोप टकटकी लगाये रहेगा।''* (क्रॉसरोड्स)

ऐसी जिनकी भूमिका, ऐसा जिनका दृष्टिकोण और वक्तव्य था, उन्हें समर्थन न देकर संयुक्त सीपीआई ने राष्ट्रीय कांग्रेस के बुर्जुआ नेतृत्व को ही मदद किया। अगर ये सही कम्युनिस्ट होते, तो ऐसा नहीं करते। आज की सीपीआई, सीपीआई (एम) को देखकर समझा जा सकता है कि उन दिनों उनके लिए इस तरह के मार्क्सवाद विरोधी आचरण करना स्वाभाविक था। इन्होंने यहां तक कि गांधीवादी नेहरू के साथ स्वर मिलाकर नेताजी जैसे देशप्रेमी को 'देशद्रोही', 'जापान का दलाल' आदि कहा था। नेताजी दूसरे विश्व युद्ध का फायदा उठाकर देश से बाहर जाकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए विदेशी ताकत की मदद लेने सबसे पहले सोवियत संघ गये थे। सोवियत नेतृत्व ने उन्हें समझाया कि उस समय फासीवादी जर्मनी–इटली–साम्राज्यवादी जापान गुट रूस पर हमल करने वाला है और रूस को उनके खिलाफ इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका के साथ एका करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में उनके लिए नेताजी की मदद कर पाना संभव नहीं है। नेताजी उनकी इस बात को समझ पाये थे और इसे लेकर उन्होंने कहीं कोई शिकायत नहीं की या कोई आरोप नहीं लगाया। वे जर्मनी होते हुए जापान गये और जापान द्वारा बंदी बनाये गये भारतीय फौजों और बर्मा तथा दूसरी जगहों पर रहने वाले भारतीयों को संगठित कर आजाद हिन्द फौज का गठन किया और लड़ाई लड़ी–जिस काम को पहले रासबिहारी बोस ने आरंभ किया था। जापान की मदद लेना उनका रणकौशल था। यह रणकौशल सही था या गलत, इसे लेकर सवाल हो सकता है। लेकिन क्या यह सोचा जा सकता है कि नेताजी जैसे देशप्रेमी ने भारत में जापानी साम्राज्यवाद की स्थापना के लिए यह काम किया था? जबकि बुर्जुआ राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व और संयुक्त सीपीआई ने ऐसा ही आरोप लगाया था।

आरएसएस (तब जनसंघ और भाजपा का जन्म नहीं हुआ था) नेतृत्व भी नेताजी का समर्थन न कर विरोध ही किया। अग्नि युग के क्रांतिकारी नेता महाराज त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती, जो 12 सालों तक अंडमान में बेड़ियों में कैद थे और बाद में पूर्वी पाकिस्तान में भी काफी दिनों तक जेल में थे, ने अपनी आत्मकथा में दुख के साथ लिखा था कि वे नेताजी के लिए समर्थन मांगने आरएसएस प्रमुख गोलवलकर के पास गये थे। लेकिन उन्हें समर्थन नहीं मिला। समर्थन नहीं मिलने के पीछे दो कारण थे। पहला, चूंकि आजादी आंदोलन हिन्दू–मुसलमान का लिहाज किये बगैर एक ही राष्ट्रीयता के गठन के आह्वान के साथ अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ संचालित हो रहा था, इसलिए आरएसएस ने इसे देशप्रेम–विरोधी प्रतिक्रियावादी मानकर विरोध किया था। वे सिर्फ हिन्दू राष्ट्र के गठन का लक्ष्य लेकर चल रहे थे, इसलिए वे आजादी आंदोलन के खिलाफ थे। इसी विचार को व्यक्त करते हुए गोलवलकर ने लिखा है, *''भूखंड आधारित राष्ट्रवाद और साझे दुश्मन के सिद्धांत हमारी राष्ट्रवादी अवधारणा की बुनियाद बन जाने के चलते आजादी के अनेक आंदोलन वस्तुतः अंग्रेज–विरोधी आंदोलन में तब्दील हो गये। इसने हमें सही हिन्दू राष्ट्रवाद की सकारात्मक और प्रेरणास्पद सोच से वंचित रखा। अंग्रेज–विरोधी आंदोलन को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का पर्याय समझा गया। समूचे आजादी आंदोलन, उसके नेताओं और आम जनता पर इस प्रतिक्रियावादी सोच ने विनाशकारी प्रभाव डाला है।''* यानी आरएसएस की नजर में अंग्रेजी साम्राज्यवाद का विरोध नहीं, बल्कि मुस्लिम विरोध और हिन्दू राष्ट्र गठन की कोशिश ही एकमात्र देशप्रेम और राष्ट्रवाद था। इसलिए उनके विचार में सिर्फ नेताजी ही नहीं, देशबंधु चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक से लेकर शहीद खुदीराम बोस, भगत सिंह, सूर्य सेन, अशफाकउल्ला खान, चन्द्रशेखर आजाद –कोई भी देशप्रेमी नहीं थे। दूसरा, नेताजी ने साम्प्रदायिकता का सख्त विरोध करते हुए कहा था, *''हमारे देश के हिन्दू–मुसलमान दोनों सम्प्रदायों के बीच विरोध का कोई चिरंतन कारण नहीं रह सकता। ऐसा है भी नहीं। ...एक तबके के खुदगर्ज लोग अपने संकीर्ण व्यक्तिगत स्वार्थ में इन दोनों कौमों के बीच तनाव और फूट डालते फिरते हैं ...ऐसे लोगों को भी आजादी आंदोलन के दुश्मनों में गिने जाने की जरूरत है। ...हिन्दू और मुसलमान का हित एक दूसरे से भिन्न है– इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। बाढ़, अकाल, महामारी तो किसी को भी नहीं छोड़ते। ...चूंकि हिन्दुस्तान में हिन्दू बहुसंख्यक हैं, इसलिए यहां हिन्दू राष्ट्र की मांग की गूंज सुनायी पड़ती है। ये सब निकम्मे दिमागों की उपज है। ..हाथ में त्रिशूल देकर संन्यासी– संन्यासिनों को हिन्दू महासभा ने वोट मांगने भेजा है। त्रिशूल और भगवा देखने मात्र से हिन्दू सिर झुका लेते हैं। धर्म का सहारा लेकर उसे कलुषित करते हुए हिन्दू महासभा ने राजनीति के मैदान में कदम रखा है। इसकी निंदा करना हर हिन्दू का फर्ज है। ...इन गद्दारों को आप राष्ट्रीय जीवन से निष्कासित कर दें। इनकी बातों पर ध्यान न दें''* (14 मई 1940, आनंदबाजार पत्रिका) नेताजी ने राजनीति में धर्म की घुसपैठ का सख्त विरोध करते हुए कहा था, *''धर्म को राजनीति से पूरी तरह अलग रखना चाहिए। धर्म व्यक्ति का बिल्कुल निजी मामला होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने पसंदीदा धर्म को मानने की पूरी आजादी रहेगी। लेकिन, धर्म या अतिन्द्रिय विषयों द्वारा राजनीति का संचालन नहीं होना चाहिए। इसका संचालन सिर्फ राजनैतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक समझ के जरिये ही होना चाहिए।''* (क्रॉसरोड्स) नेताजी के नेतृत्ववाले आजाद हिन्द फौज में धर्म की कोई जगह नहीं थी और प्रधान सेनापति से लेकर कुछ महत्वपूर्ण पदों पर योग्यता के अनुसार मुसलमान थे। क्या इस नेताजी को भाजपा का जनक आरएसएस समर्थन कर सकता है? यहां जिक्र किया जा सकता है कि भारत के आजादी आंदोलन में सुभाष चन्द्र बोस के खिलाफ कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेतृत्व, आरएसएस और संयुक्त सीपीआई ने जो कलंकित भूमिका निभायी थी, उसका इतिहास में जिक्र नहीं है। ऐसा इसलिए कि देश की जनता को इन बातों की जानकारी न हो।

आज देश की तस्वीर क्या है? गणतंत्र दिवस पर जब जंगखोर अमेरिकी राष्ट्रपति का अभिनन्दन हो रहा है; रोशनी में झिलमिलाते राष्ट्रपति भवन में; राज्यों के राजभवनों में; सरकारी भवनों में; राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और उद्योगपतियों की मौजूदगी में खुशियां मनायी जा रही हैं;

(शेष पृष्ठ 7 पर)

शिक्षा-विरोधी नीतियों के खिलाफ एआईडीएसओ का प्रदर्शन

दिल्ली: सीबीसीएस, आरयूएसए और केन्द्रीय विवि बिल के खिलाफ ऑल इण्डिया डीएसओ की दिल्ली राज्य कमेटी ने 8 जून को विरोध प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से जुलूस शुरू हुआ और एसजीटीबी खालसा कॉलेज पर जाकर समापन हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने रैली में हिस्सा लिया और सरकार की छात्र-विरोधी और शिक्षा-विरोधी नीतियों के खिलाफ जम कर नारे लगाये। ऑल इण्डिया डीएसओ के दिल्ली राज्य सचिव कॉमरेड प्रशांत कुमार, राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड कृष्णेन्दु मुखर्जी, लेडी श्रीराम कॉलेज से कल्पना यादव, विवेकानंद कॉलेज से श्रेया सिंह और मोतीलाल नेहरू कॉलेज से अशरफ ने प्रदशनकारियों को सम्बोधित किया।

दिल्ली में प्रदर्शन करते एआईडीएसओ कार्यकर्ता

वक्ताओं ने कहा कि तथाकथित सुधारों के नाम पर सरकार लगातार ऐसी नीतियाँ लागू कर रही है जो भारत में जनता के पैसों से चल रही शिक्षा व्यवस्था को हल्का कर रही हैं और शिक्षा के तेजी से व्यापारीकरण के दरवाजे खोल रही हैं। वक्ताओं ने यह भी कहा कि शिक्षा का भगवाकरण भी सरकार के एजेण्डे पर है और यह बात साफ जाहिर है कि कैसे आधुनिक विज्ञान के साथ पौराणिक कथाओं का घालमेल किया जा रहा है और इतिहास को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है। छात्रों और शिक्षकों के जनवादी अधिकारों को छीना जा रहा है और जनवादी बॉडियों को सरकार के हाथों की कठपुतली में तब्दील किया जा रहा है। सीबीसीएस, आरयूएसए और केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिल इस प्रक्रिया को और भी तेज करेंगे।

वक्ताओं ने छात्रों और शिक्षाप्रेमी लोगों से शिक्षा पर भीषण हमले की इस घड़ी में आगे आने और अपनी आवाज बुलंद करने और सरकार व प्रशासन की इन सब शिक्षा-विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार छात्र आन्दोलन गठित करने की अपील की।

शिक्षा पर परिचर्चा

परिचर्चा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड प्रताप सामल

जबलपुर(म.प्र.) : ऑल इण्डिया शिक्षा बचाओ समिति (एआईएसईसी) की जबलपुर शाखा ने 29 मई को रानी दुर्गावती संग्रहालय सभागार में शिक्षा पर परिचर्चा का आयोजन किया। इसमें काफी सारे प्रबुद्ध नागरिकों, बुद्धिजीवियों और शिक्षाप्रेमी लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर बोलते हुए जानी मानी समाजसेविका रिटायर्ड अध्यापिका श्रीमती साधना उपाध्याय ने 1.21 लाख सरकारी स्कूलों को पीपीपी के तहत निजी हाथों में देने के म.प्र. सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की। शिक्षविद प्रोफेसर श्रीमती भारती शुक्ला ने दर्शाया कि कारपोरेटों के स्वार्थ में काम करने वाली सरकार की शह से शिक्षा आज छात्रों को तर्कशील बनाने की बजाय अतार्किक और मशीनी मानव बनाती है। मुख्य वक्ता एआईएसईसी के अखिल भारतीय सचिवमण्डल सदस्य प्रताप सामल ने कहा कि आज केन्द्र व राज्य सरकार का चौतरफा हमला लोगों की शिक्षा का संकोचन करने और शिक्षा को अधिकाधिक मुनाफा लूटने के लिए कारपोरेट घरानों के लिए खुला मैदान बनाने पर लक्षित है। साथ ही साथ केन्द्र की नई सरकार शिक्षा का साम्प्रदायीकरण करने की भी कोशिश कर रही है। वे पौराणिक कथाओं को इतिहास के तौर पर पेश करने के लिए अपनी सनकों और कपोल कल्पनाओं के मुताबिक इतिहास का पुनर्लेखन और तोड़मरोड़ कर रहे हैं। इस तरह वे फासीवाद के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा को बचाने के लिए जोरदार जन आन्दोलन खड़ा करने की लोगों से अपील की।

परिचर्चा में समिति के जबलपुर शाखा के सहसचिव एडवोकेट विनायक शाह, डी के श्रीवास्तव, महिला नेत्री चन्द्रा पात्रा और छात्र नेता मुदित भटनागर ने भी अपने विचार व्यक्त किये। अध्यक्षता म.प्र. शिक्षा बचाओ कमेटी के संयोजक डा. रामावतार शर्मा ने की और संचालन जबलपुर की समिति के सह संयोजक पोषण प्रसाद कुशवाहा ने किया। सभा में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

स्कूलों के निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन

अशोकनगर (म.प्र.) : म.प्र. के 1 लाख 21 हजार सरकारी स्कूलों को निजी कम्पनियों के हाथों में सौंपने के सरकार के शिक्षा-विरोधी फरमान के खिलाफ स्थानीय गांधी पार्क पर 20 मई को ऑल इण्डिया डीएसओ द्वारा एक जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें संगठन की जिला उपाध्यक्ष बबीता समर ने कहा कि म.प्र. में शासकीय स्कूलों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ नहीं है। लायब्रेरी, लैब, शौचालय व खेल मैदान की कमी है। शिक्षकों को विद्यालयों में पढ़ाने के काम में कम और वोटिंग, पशु गणना, जनगणना आदि के काम में ज्यादा लगाये रखा जाता है।

स्कूलों को निजी हाथें में देने का विरोध करते लोग

छात्र संगठन की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं जिला सचिव अजीत पवार ने कहा कि सरकार शिक्षा का बजट लगातार घटाती जा रही है और शासकीय स्कूलों को संचालित करने में पैसे की कमी का तर्क देकर इनको निजी हाथों में सौंपने जा रही है। शिक्षक व कवि सुरेन्द्र रघुवंशी ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने स्कूलों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा है जो शिक्षा को आम लोगों की पहुंच से बाहर कर देने वाला शिक्षा-विरोधी फरमान है। उन्होंने छात्रों, शिक्षकों और शिक्षाप्रेमी लोगों से इसका पुरजोर विरोध करने की अपील की।

प्रदर्शन में सावन बैरागी, कृष्णा, श्याम शाक्य, देवेन्द्र, विक्की, कमलेश, अनुराग, नंदनी सहित संगठन के विभिन्न कार्यकर्ता उपस्थित थे।

महंगाई, बेरोजगारी, भूमि की लूट, मजदूरों, किसानों व महिलाओं पर हमले, भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध, शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण और साम्प्रदायिकता के खिलाफ मध्य प्रदेश में वामपंथी पार्टियों की तरफ से आयोजित राज्य स्तरीय संयुक्त सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए एसयूसीआई(सी) के म.प्र. राज्य सचिव कॉमरेड प्रताप सामल

पिलानी में स्टडी सर्कल

कॉमरेड शिवदास घोष की पुस्तक 'सांप्रदायिकता की समस्या के प्रसंग में' पर 23 मई को पिलानी (राजस्थान) की अग्रसेन धर्मशाला में एसयूसीआई (सी)पार्टी की ओर से एक अध्ययन किया गया, इस पर चर्चा हुई। यह चर्चा कामरेड प्रतिभा नायक एवं कामरेड रामफल सुहाग की मौजूदगी में सम्पन्न हुई। 24 मई को स्थानीय अग्रसेन धर्मशाला में ही पार्टी की एक आम सभा का आयोजन किया गया। सभा को पार्टी की केन्द्रीय कमेटी सदस्य एवं हरियाणा राज्य कमेटी के सचिव, कामरेड सत्यवान ने सम्बोधित किया। उन्होंने सांगठनिक विषयों पर विस्तार से बात रखी।

स्टडी क्लास लगाई गई

दुर्ग (छ.ग.) : सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष की पुस्तक, *मार्क्सवाद और मानव समाज का विकास* पर एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) द्वारा दुर्ग के कुटला भाटा गांव में तीन दिन की स्टडी क्लास लगाई गई जो 26 मई को सम्पन्न हुई। अंतिम सत्र में पार्टी के जिला प्रभारी कॉ विश्वजीत हारोडे ने पुस्तक के कुछ बिन्दुओं को सबके सामने रखा।

राज्य के पार्टी कार्यकर्ताओं को वैचारिक तौर पर लैस करने के मकसद से लगाये गये इस शिक्षण शिविर से इसमें भाग लेने वालों में नये जोश का संचार हुआ।

बकाया मानदेय का भुगतान न किये जाने पर ग्रामीण सफाई कर्मियों ने किया रोष प्रदर्शन

नारनौल में रोष प्रदर्शन करते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारी

नारनौल, हरियाणा: ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने बकाया वेतन के भुगतान को लेकर 11 जून को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रोष जताया। इससे पहले ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन (सम्बधित एआईयूटीयूसी) की ओर से जिला प्रधान जुगेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में स्थानीय चितवन वाटिका में सभा हुई। इसका संचालन महेन्द्र सिंह ने किया। उसके उपरांत सफाई कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए लघुसचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में ग्रामीण सफाई कर्मियों का सरकारी कर्मचारी घोषित करने, 15000 रुपये मासिक न्यूनतम बेतन देने, साल में दो ड्रैस लागू करने, सफाई के उपकरण व गैस मास्क उपलब्ध कराने, बीमा, पेन्शन व भविष्य निधि आदि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, मानदेय का समय पर भुगतान करने आदि की मांग की गई।

प्रदर्शनकारियों को ऑल इण्डिया यूटीयूसी के जिला सचिव कॉ. सुभाष चंद्र, ऑल इण्डिया यूटीयूसी के जिला प्रधान कॉ. शेरसिंह, यूनियन के प्रधान जुगेन्द्र कुमार और हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के महासचिव मास्टर सूबे सिंह ने सम्बोधित किया। इस अवसर पर बिजेन्द्र सिंह, अशोक, मुकेश, बाला, मंजू देवी सहित काफी सारे सफाई कर्मचारी उपस्थित थे।

पेयजल समस्या के जल्द समाधान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा

सागर(म.प्र.): जन समस्या संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में 9 जून को पेय जल समस्या के शीघ्र निराकरण हेतु आयुक्त एवं कलेक्टर सागर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन मे मॉग की गयी कि तिली बाघराज वार्ड की लाल टौरिया पर लंबे समय से पेयजल समस्या व्याप्त है। प्रशासन द्वारा उक्त समस्या के निराकरण हेतु कोई ध्यान नही दिया जा रहा हैं। उक्त लाल टोरिया पर 95 प्रतिशत गरीब मेहनतकश जनता निवास करती है जिसके पास शौचालय नही है। उक्त क्षेत्र में बना सुलभ शौचालय भी पानी न मिलने से सुचारू रूप से संचालित नही हो पा रहा है एवं केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सभी के पास शौचालय हो तभी कारगार होगी जब सबको पानी की सुव्यवस्थित एवं सुचारू व्यवस्था हो। जिससे उक्त क्षेत्र में ओवर हेड टैन्क बनाया जाये एवं मोटी पाइप लाइन डाली जाये ताकि सभी को पानी प्राप्त हो सके। उक्त पेयजल समस्या का शीघ्र निराकरण किया जाये अन्यथा जनसमस्या संघर्ष मोर्चा जनता को संगठित कर सड़कों पर जन आंदोलन करने को मजबूर होगा।

ज्ञापन में मोर्चा के संयोजनकर्ता गणेश पटेल, तुलसी चढार, एवं कानूनी मार्गदर्शन केन्द्र के जिला समन्वयक सुशील कुमार पटेल, रामसिंह कुशवाहा, जयश्री चढार, जीतू पटेल एवं अन्य लोग शामिल थे।

झूठे मुकदमें वापस लेने और गरीब छात्रों को दाखिला देने की उठी मांग

सोनीपत में रोष प्रदर्शन करते हुए एसयूसीआई(सी), एआईडीएसओ व नौजवान भारत सभा के कार्यकर्ता

सोनीपत : हरियाणा प्रान्त में गरीब परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में धारा 134-ए के अर्न्तगत मुफ्त शिक्षा के लिए एक आन्दोलन चल रहा है। कुछ संगठन इसके लिए बच्चों को दाखिला दिलवाने के लिए प्राइवेट स्कूलो में बच्चों व अभिभावको के साथ जा रहे थे। इसलिए प्राइवेट स्कूल संचालको व सरकार ने इस आन्दोलन को बढ़ता हुआ देख कर इसको दबाने की योजना बनाई। 18 मई को छात्र अभिभावक संघ के संचालक विमल किशोर के नेतृत्व में लोग स्पिरिंग बर्ड स्कूल से निकाले गए गरीब बच्चों को दाखिला दिलवाने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय प्राइवेट स्कूल संचालकों ने पूलिस से सांठगांठ कर 40 अभिभावको को झूठे मुकदमें बनवा कर गिरफ्तार करा दिया जिनमें 26 महिलाएं व 14 पुरुष थे। इन पर हत्या के प्रयास, स्कूल में आग लगाने, अध्यापिकाओं से छेड़खानी व तोड़फोड़ जैसी गैरजमानती धाराएं लगाकर इनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। इसके पीछे बीजेपी व उसके नेताओं का पूरा हाथ था क्योकि वे भी निजी शिक्षण संस्था चला रहे है। इस पुलिस जुल्म व झूठे केस बनाने के विरोध में 25 मई को एसयूसीआई(सी), नौजवान भारत सभा और ऑल इण्डिया डीएसओ के कार्यकर्ताओं ने सोनीपत शहर में जोरदार जुलूस निकाला। उसी दिन महिलाओं की जमानत मंजूर हो गई। आन्दोलन को तेज करने के लिए 2 जून को तीन सौ से ज्यादा लोगों द्वारा उपायुक्त कार्यालय पर धरना दिया गया। आन्दोलन के दबाव में बाकी लोगों को भी रिहा कर दिया गया। 4 जून को आन्दोलनकारियों की रिहाई पर शहर में स्वागत जुलूस निकाला गया। शहर मे कई जगह लोगो ने आन्दोलनकारियों का स्वागत किया। शिक्षा बचाओ आन्दोलन को व्यापक बनाने के लिए विभिन्न संगठनो द्वारा शिक्षा बचाओ मंच का निर्माण किया गया। सबको शिक्षा सुलभ कराने, वैज्ञानिक, जनवादी व धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देने, धारा 134-ए कारगर ढंग से लागू कर गरीब परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला देने, झूठे केस वापिस लेने, शिक्षा का निजीकरण व व्यापारीकरण रोकने की मांग को लेकर शिक्षा बचाओ मंच की तरफ से 28 जून को जिला न्यायालय परिसर में शिक्षा सम्मेलन किया जायेगा।

पुनर्जागरण काल के मनीषी राममोहन राय को किया याद

जबलपुर (म.प्र.) : 22 मई को ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन, जबलपुर इकाई ने पुनर्जागरण काल के महान मानवतावादी राममोहन राय की 243वीं जयंती पर उनको श्रद्धा के साथ याद किया। सर्वप्रथम श्रीमती सरिता झा ने राममोहन राय के जीवन-संघर्ष पर प्रकाश डाला। उसके बाद संगठन की जिला अध्यक्ष श्रीमती चन्द्रा पात्रा ने अपने भाषण में कहा कि राममोहन राय ने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुप्रथाओं, कुरीतियों और अंधविश्वास दूर करने के लिए अपनी जिन्दगी लगा दी थी। महिलाओं के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार जैसे, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, सती प्रथा बंद कराने में उन्होंने अग्रणी भूमिका अदा की। पैतृक सम्पत्ति में नारियों को हक दिलाने, विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनवाने और मध्ययुगीन अंधकार से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा और नारियों को भी शिक्षा लागू करवाने की पैरवी की। पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के माध्यम से उन्होंने जनमानस में सोच-विचार करने का ढंग बदलने, तर्कसंगत मानसिकता पैदा करने और रूढ़िवाद व जातिवाद से मुक्त करने का प्रयास किया। उनके जीवन-संघर्ष से सीख लेकर वर्तमान में सामाजिक प्रगति में अपनी भूमिका निभा कर ही हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त कर पायेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ सभा सम्पन्न हुई। सभा में श्रीमती मनोरमा उदैनिया, शारदा डेविड, साधना सेठी, सरिता झा, प्रेमलता झा, गोदावरी बलैया उपस्थित थी।

बिजली के निजीकरण के खिलाफ राजस्थान में प्रदर्शन करते हुए एसयूसीआई (सी) कार्यकर्ता, बिजली अधिनियम 2003 रद्द करने की मांग की।

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ किसान आन्दोलन की राह पर

मुरादाबाद (उ.प्र) : मोदी सरकार के काले फरमान, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश /बिल, फसलों के मुआवजे में भेदभाव व भ्रष्टाचार, बिजली आपूर्ति में कमी, गन्ना के बकाया के भुगतान में देरी के खिलाफ 17 जून को ऑल इण्डिया कृषक खेतमजदूर संगठन द्वारा स्थानीय रेलवे स्टेशन से लेकर कमिश्नर कार्यालय तक जुलूस निकाला गया। इसकी अगुआई शील कुमार(जोया), कमल सिंह (ज्ञानपुर), देवराज सिंह (कृषक नगर), दिग्गज सिंह (सरकड़ी अजीज, धर्मपाल सिंह (मड़ैया) मूलचंद सिंह गिल(भारापुर काफी), सूरजपाल(महराणा) समेत कई किसान नेताओं ने की। किसान संगठन ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार के नाम कमिश्नर मुरादाबाद को सौंपा।

ज्ञापन में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश/बिल रद्द करने, बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा देने, आत्महत्या करने वाले किसानों के हर परिवार को 11 लाख रुपये देने, गन्ने के बकाया का तुरन्त भुगतान करने, 24 घण्टे बिजली की सप्लाई देने, घरेलू बिजली 2 रुपये यूनिट करने, किसान-खेतमजदूरों के सारे कर्ज माफ करने और एसईजैड मुरादाबाद व नेपा पेपर मिल अलीगंज के लिए अधिग्रहीत जमीन किसानों को वापस देने की मांग की गई। धरना सभा को संगठन के अखिल भारतीय संगठक कॉ. सत्यवान के अलावा एआईयूटीयूसी के प्रदेश सचिव कॉ. विजयपाल सिंह ने भी सम्बोधित किया।

अशोकनगर : भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ में सड़कों पर उतरे एआईकेकेएमएस कार्यकर्ता

अशोकनगर (म.प्र.) : किसानों से उनकी जमीन जबरन छीनने के काले फरमान के खिलाफ 16 मई को ऑल इण्डिया कृषक खेतमजदूर संगठन द्वारा एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। धरने को संगठन के राज्य सचिव कॉमरेड मनीष श्रीवास्तव व जिला प्रभारी रामसिंह मदरैय और एसयूसीआई(सी) के जिला प्रभारी कॉ. सचिन जैन ने सम्बोधित किया।

सुजड़ौला (राजस्थान) : भूमि अधिग्रहण अध्यादेश व बिजली की समस्या को लेकर किसानं परेशान हैं। खाद, बीज, कीटनाशक, बिजली-पानी और डीजल आदि खेती में काम आने वाली सभी चीजों के दाम बढ़ते जाने और किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य न मिल पाने से किसानों की दुर्दशा बढ़ती जा रही है। इन समस्याओं के खिलाफ आन्दोलन गठित करने और संगठन को मजबूत करने के लिए ऑल इण्डिया केकेएमएस की ओर से 15 जून को झुंझनूं जिला के गांव सुजड़ौला में किसानों की सभा आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता संगठन के नेता कॉ. सरदारा सिंह ने की। सभा के मुख्य वक्ता एसयूसीआई(सी) हरियाणा राज्य कमेटी सदस्य कॉ. रामफल थे। सभा का संचालन कॉ. सुभाष ने किया। सभा की शुरूआत में विश्वेश्वर लाल ने जनगीत सुनाये।

फुलवारी शरीफ, पटना : केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये किसान व जनविरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, महंगाई, बेरोजगारी व शिक्षा के गिरते स्तर के खिलाफ 21 मई को पटना के फुलवारी शरीफ स्थित शहीद भगत सिंह चौक से एक प्रतिरोध जूलूस निकाला गया जो फुलवारी शरीफ प्रखंड कार्यालय तक गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम एक स्मार पत्र सौंपा।

प्रखंड कार्यालय पर आयोजित सभा को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पटना जिला सचिव कॉ० साधना मिश्रा, राजेन्द्र राय, वैद्यनाथ शर्मा, अरूण कुमार आदि ने संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता सुरेश कुमार ने की।

आईसीडीएस स्कीम बंद करने की योजना के खिलाफ
आगंनवाड़ी कर्मियों ने किया मुरादाबाद मंडल के सांसदों का घेराव

अमरोहा (उ.प्र.) : जनहित की समेकित बाल विकास योजना(आईसीडीएस) में केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा भारी कटौती किये जाने और इसे बंद करने के वित्त मंत्रालय के फैसले के खिलाफ एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसियेशन, उ.प्र. का आन्दोलन कई दिनों से जारी है।

इसी क्रम में मुरादाबाद मंडल के सांसदों के घेराव कार्यक्रम में 7 जून को अमरोहा के सांसद कंवर सिंह तंवर का घेराव करने के लिए आंगनवाड़ी कर्मी सैकड़ों की संख्या में जुटी। पुलिस द्वारा उनके टैण्ट उखाड़ दिये गये। इससे नाराज आंगनवाड़ी कर्मियों ने जिला अधिकारी कार्यालय को घेर लिया। जोरदार प्रदर्शन कर अपना रोष जताया और सांसद के नाम अपना मांगपत्र डीएम अमरोहा को सौंपा।

अमरोहा में सांसद के घेराव के लिए जुटी आगनवाड़ी वर्कर

रामपुर में आंगनवाड़ी कर्मियों द्वारा सांसद के घेराव कार्यक्रम में बोल्ते हुए सांसद नैपाल सिंह

वहां हुई सभा को एसोसियेशन की मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष सोमवती शर्मा, मुरादाबाद से कमलेश चाहल, अमरोहा जिला अध्यक्ष सत्यबाला चौधरी, सचिव माया चौहान, कल्पना शर्मा, रेखा सिंह, रजनी दिवाकर, प्रदेश महासचिव शशिबाला, एआईयूटीयूसी के राज्य सचिव कॉ. विजयपाल सिंह, एआईडीवाईओ के प्रदेशाध्यक्ष हरकिशोर सिंह, उपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ने सम्बोधित किया।

रामपुर में 7 जून को सांसद नैपाल सिंह के घेराव कार्यक्रम में सांसद को आम जन के बीच आना पड़ा। आंगनवाड़ी कर्मियों ने उनको अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। सांसद ने उनके आन्दोलन में पूरा सहयोग देने का वादा किया। कार्यक्रम का नेतृत्व एसोसियेशन की मंडल सचिव तथा रामपुर की जिलाध्यक्ष मिथलेश चौधरी और मंडल अध्यक्ष सोमवती शर्मा ने किया। कमलेश चाहल, शशिबाला, रेखा सिंह, ओमवती, पूनम बिश्नोई, सत्यबाला चौधरी, रजनी दिवाकर, भूरी देवी, समीना बी, छवि राय, आदि सहित हजारों आंगनवाड़ी कर्मी इसमें शामिल हुई।

एआईडीवाईओ ने की स्टडी क्लास

भिवानी (हरियाणा) : ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन, हरियाणा राज्य कमेटी द्वारा 30 व 31 मई को सैनी धर्मशाला में सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष की पुस्तक, 'बेरोजगारी की समस्या और सांस्कृतिक स्तर के पतन का समाधान किस रास्ते' पर दो दिन का स्टडी सर्कल आयोजित किया गया। इसका संचालन एसयूसीआई(सी) के केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉ. सत्यवान ने किया। एआईडीवाईओ की महासचिव कॉ. प्रतिभा नायक और पार्टी के भिवानी जिला सचिव कॉ रामफल भी इसमें मौजूद रहे।

ऑल इण्डिया एमएसएस का राज्य स्तरीय शिक्षण शिविर सम्पन्न

ग्वालियर (मध्य प्रदेश) : 5, 6, 7 जून को ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन का राज्य स्तरीय शिक्षण शिविर यहां सम्पन्न हुआ। इसमें 9 जिलों से 35 कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की। कॉमरेड शिवदास घोष की पुस्तक 'मार्क्सवाद और मानव समाज का विकास' और 'नारी मुक्ति के प्रसंग में' लेख पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। शिक्षण शिविर का संचालन संगठन की सर्वभारतीय अध्यक्ष कॉ. छाया मुखर्जी ने किया।

चर्चा के दौरान महिला आरक्षण, तलाक होने पर भरण-पोषण के सम्बन्ध में धारणा, वैश्यावृत्ति को कानूनी बनाए जाने की साजिशाना कोशिश आदि तमाम विषयों पर भी सार्थक बहस हुई। कार्यकर्ताओं की रुचि अनुसार प्रेरणाप्रद जनगीत और नाटक का भी प्रशिक्षण दिया गया। सवेरे जल्दी उठना, व्यायाम करना, साफ-सफाई करना आदि दैनंदिन क्रम द्वारा अनुशासन और सामूहिकता का वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया। 5वें सत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक की गई जिसमें रखी गई रिपोर्ट से प्रदेश में संगठन की स्थिति व काम में आ रही समस्याओं से नेतृत्व को अवगत कराया गया। इस बैठक में कॉ. छाया मुखर्जी के साथ एसयूसीआई(सी) के मध्य प्रदेश राज्य सचिव कॉ. प्रताप सामल भी उपस्थित रहे।

दुर्ग में एआईडीएसओ ने लगाया समर कैम्प

किसी भी समाज की प्रगति के लिए शिक्षा-संस्कृति महत्वपूर्ण अंग है। इनके बगैर सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन आज समाज विभिन्न समस्याओं से पीड़ित है और लगातार प्रदूषित हो रहा है। शिक्षा व संस्कृति में लगातार गिरावट ने इसे और भी भयावह बना दिया है। मीडिया व इंटरनेट के माध्यम से अश्लीलता परोसी जा रही है, वहीं छात्र-नौजवानों में वैज्ञानिक चेतना विकसित न हो सके इसलिए उन्हें नशे में डूबोकर उनमें अंधविश्वास फैलाया जा रहा है जिसका असर पूरे समाज के साथ-साथ हमारे घरों पर भी हो रहा है। छात्रों में फूहड़ संस्कृति, खाओ पियो मौज करो की मानसिकता पनपायी जा रही है। छात्र-नौजवानों में सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति, चरित्र निर्माण और वैज्ञानिक चेतना विकसित करने के उद्देश्य से ऑल इण्डिया डी.एस.ओ. छ.ग. राज्य इकाई के द्वारा 8 व 9 जून को दो दिवसीय समर कैम्प का आयोजन राजेन्द्र पार्क, दुर्ग में किया गया। इस समर कैम्प में स्पोर्ट्स, हैण्डीक्राफ्ट, पेन्टिंग, रंगोली, गाना, ड्रामा प्रतियोगिता आयोजित कर विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये गये। पुरस्कार वितरण में मुख्य अतिथि डॉ. रितेश वाल्मिकी, डॉ. सतीश चंद्राकर रहे। इस समर कैम्प में 205 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।

शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ एआईडीएसओ ने की रैली

झुंझुनूं (राजस्थान) : ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेन्ट्स आर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) ने 15 जून को यहां कलेक्ट्रेट पर छात्र रैली की और कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर शिक्षा का निजीकरण और साम्प्रदायीकरण बंद करने की मांग की। संगठन के प्रदेश सचिव दीपक दहिया ने कहा कि स्कूलों में पास-फेल प्रणाली बंद करने से शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। शिक्षा का निजीकरण-व्यापारीकरण करने से शिक्षा गरीब ही नहीं, बल्कि मध्यम वर्गीय परिवारों के छात्र-छात्राओं से भी दूर होती जा रही है। सेमेस्टर प्रणाली शुरू करने से एक कोर्स की टुकड़ों में पढ़ाई की ज्यादा फीस ली जा रही है।

ज्ञापन देन वालों में राहुल शर्मा, सुरेन्द्र कुमार, विकास, मुकेश कुमार, ओजस्वी, राकेश, नवीन सिंह, भुवनेश्वर, विकास पुनिया आदि मौजूद थे।

शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण का विरोध करते एआईडीएसओ कार्यकर्ता

प्रायोगिक परीक्षा के नाम पर किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ
छात्रों ने किया रोष प्रदर्शन

मुरादाबाद (उ.प्र) : स्थानीय महाराजा हरिश्चन्द्र डिग्री कॉलेज में प्रायोगिक परीक्षा के नाम पर छात्रों के पिछले कई वर्ष से किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ एआईडीएसओ की जिला कमेटी के नेतृत्व में कला संकाय के छात्रों द्वारा आन्दोलन चलाया गया था। इसमें रूहेलखण्ड वि.वि. बरेली के कुलसचिव ने छात्रों की मांग से सहमत होते हुए गत 16 अप्रैल को एसोसियेट प्रोफेसर डॉ. रवीश कुमार को आंतरिक परीक्षक से हटाते हुए डा. नरेन्द्र सिंह को आंतरिक परीक्षक नियुक्त करने के आदेश कॉलेज के प्राचार्य को दिए थे। लेकिन अपनी हठधर्मिता तथा राजनैतिक सम्बंधों का सहारा लेकर प्राचार्य पिछले एक माह से छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा को टाल रहे हैं और वि.वि. कुलसचिव के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं।

इसके खिलाफ कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने एआईडीएसओ की जिला कमेटी के नेतृत्व में 14 मई को जिला अधिकारी कार्यालय मुरादाबाद पर रोष प्रदर्शन किया तथा डीएम से हस्तक्षेप की मांग की। डीएम से हुई वार्ता में ऋतु चौधरी, फैज खान, शाने आलम, प्रांशी गुप्ता शामिल थे। डीएम महोदय ने कहा कि वे वि.वि. कुलसचिव के आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे।

मुरादाबाद में रोष प्रकट करते हुए एआईडीएसओ कार्यकर्ता

फीस वृद्धि के खिलाफ हजारीबाग बंद

हजारीबाग : 27 अप्रैल को निजी स्कूलों की मनमानी और राज्य सरकार की उदासीनता के खिलाफ एक दिवसीय बंद सफल हुआ। विदित हो कि अभिभावक संघ एवं विभिन्न जनसंगठनों के द्वारा एक महीने से ज्यादा से आन्दोलन चलाया जा रहा था। आन्दोलन के क्रम में मशाल जुलूस, धरना और उसके बाद हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हजारों हस्ताक्षर के साथ-साथ जनसंपर्क अभियान चलाया गया।

बन्द के दौरान ही उपायुक्त ने वार्ता हेतु निमंत्रण दिया। 13 सूत्री मांगों में से 6 पर सार्थक चर्चा के बाद वार्ता समाप्त हुई। इस आन्दोलन में एआईडीएसओ एवं एआईएमएसएस ने अग्रणी भूमिका निभायी।

मिड डे मील कार्य को निजी कम्पनी को सौंपने का विरोध

रिवाड़ी : मिड डे मील के लिए फूड सप्लाई का काम निजी कम्पनी को सौंपे जाने के फैसले के खिलाफ एआईयूटीयूसी से सम्बन्धित मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ता 15 जून को रेवाड़ी में राव तुलाराम पार्क में एकत्रित हुई। वहां से उपायुक्त कार्यालय तक जुलूस निकाला और उपायुक्त रेवाड़ी की मार्फत मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व प्रधान सुरस्ती देवी और महासचिव ओमवती ने किया। यूनियन के प्रान्तीय सलाहकार कॉमरेड राजेन्द्र सिँह ने प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित किया।

क्रांतिकारी शहीद प्रीतिलता की जन्यंती पर
महिलाओं ने की विचार गोष्ठी

इलाहाबाद (उ.प्र) : 3 मई को इलाहाबाद में ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन के द्वारा प्रथम क्रांतिकारी महिला शहीद प्रीतिलता के जन्म दिवस के अवसर पर ''प्रीतिलता और आज की महिलाओं का दायित्व'' विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।

सर्वप्रथम लता शर्मा ने प्रीतिलता के जीवन-संघर्ष और विचारों को विस्तार से रखा। ज्ञानशीला शर्मा ने आज से सौ वर्ष पहले पराधीन भारत के समाज में महिलाओं की दुखद स्थिति से आज के समय की तुलना करते हुए बताया कि आज गोरी बुराई तो देश को छोड़ कर चली गयी, लेकिन आज भी महिलाओं की स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आया है। आज महिलाएं सामंती शोषण के साथ-साथ पूंजीवादी व्यवस्था में जकड़ कर दोहरे शोषण का शिकार हैं। सुधा त्रिपाठी ने कहा कि यहां के शासक, नेता, अफसर, पुलिस कोई भी हो, सभी महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। सामंती सोच होने की वजह से इन सभी का दृष्टिकोण नारी-विरोधी है। रश्मि मालवीय ने कहा कि इन स्थितियों में नारी को समाज में अपना मान-सम्मान और सही स्थान पाने के लिये खुद आगे आकर लड़ाई लड़नी होगी। इसके लिये उन्हें देश की आधी आबादी को संगठित करना होगा।

चर्चा में कल्याणी रायचौधरी, गीता त्रिपाठी, कुसुम सिंह, शिखा श्रीवास्तव, रेनू, संध्या, रामपति, राजलक्ष्मी आदि ने भी हिस्सा लिया। संचालन रश्मि मालवीय ने किया।

महान क्रांतिकारी नेताजी...

(पृष्ठ 2 का शेष)

उत्सव हो रहे हैं; भोज हो रहे हैं; तब वहां से कूड़ेदान में फेंकी गई जूठन को इकट्ठा करने के लिए फूटपाथ पर रहने वाले बच्चे छीना-झपटी कर रहे हैं। भोजन, शिक्षा, चिकित्सा से वंचित आज लाखों बच्चे फूटपाथों पर रहते हैं। आबादी के 120 करोड़ वाले अपने देश में राष्ट्रपति की स्वीकारोक्ति के मुताबिक 66 करोड़ बेरोजगार हैं, कई करोड़ मजदूरों को काम से हाथ धोना पड़ा है, 77 प्रतिशत लोगों की रोजाना की आमदनी मात्र 20 रुपये है, साल में लाखों लोग भूख, से, बिना इलाज के मर रहे हैं। लाखों लोग कर्ज में फंसकर भूख न मिटा पाने की वजह से आत्महत्याएं कर रहे हैं। लाखों महिलाओं और बच्चों की तस्करी हो रही है। गरीबी की पीड़ा न झेल पाने के चलते लाखों महिलाएं अपना जिस्म बेचने को मजबूर हैं। रोजाना शहरों-गांवों में हजारों बलात्कार की शिकार महिलाएं बिलख कर रही हैं। यही है भारतीय प्रजातंत्र में प्रजा का हाल! दूसरी तरफ रोजाना हर मिनट पर देशी-विदेशी पूंजीपति, बड़े व्यवसायी-जमाखोर-कालाबाजारी जनता का खून चूसकर करोड़ों का मुनाफा बटोर रहे हैं, देश-विदेश के बैंकों में अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, विदेशों में और देश में बड़े-बड़े आलीशान महल बना रहे हैं, महंगे होटलों में रंगरेलियां मना रहे हैं। क्या यह वही आजादी है, जिसके लिए नेताजी ने अपना सर्वस्व देकर संघर्ष किया था?

काफी दिनों तक 'गरीबी हटाओ' का नारा देकर कांग्रेस ने देश का यह हाल किया है। फिर उसकी जगह पर 'सुशासन', 'अच्छे दिन' का वादा कर भाजपा ने सत्ता में जाते ही एक झटके में ट्रेन सहित यात्री परिवहन के भाड़े में बढ़ोतरी कर दिया और यह ऐलान कर दिया कि वे आगे और बढ़ायेंगे। उन्होंने दवाओं की कीमतें बढ़ायी तथा शिक्षा व स्वास्थ्य बजट में कटौती की। खाद्यान्न-डीजल-किरासन पर सब्सिडी और 100 दिनों के काम में कटौती की गयी। उन्होंने किसानों की अनुमति लिये बगैर मालिकों के हित में उपजाऊ-अनुपजाऊ जमीन का लिहाज किये बगैर उन पर कब्जा करने का एलान किया है, मालिकों को बेहिचक मजदूरों की छंटनी का अधिकार दिया है, मजदूरों के संघर्ष के अधिकार छीन लिया है। चीजों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकारी कार्यालयों में नयी नियुक्तियों पर रोक लगाई हुई है। गरीबों पर तरह-तरह के हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ मालिकों के लाखों करोड़ रुपये के बकाये टैक्स और कर्ज सरकार माफ कर रही है। उनके टैक्सों में कटौती कर रही है। सरकारी कारखाने और खदान उन्हें ओने-पाने भाव दे रही है। इसलिए मालिकों के अच्छे दिन आये हैं जबकि गरीबों तथा आम अवाम के लिए और भयावह दुर्दिन आये हैं।

जनता को जानना चाहिए कि वोट के जरिये सरकारें बदलती हैं, लेकिन पूंजीवादी शोषण में परिवर्तन नहीं होता है। पूंजीपति ही इस देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति, राज्य, सरकार—सब कुछ चलाते हैं। भाजपा, कांग्रेस, क्षेत्रीय पार्टियां और सीपीआई (एम) जो भी सत्ता में जायें, वे सरकारी पार्टियां उन्हीं के हुक्म पर सरकार चलाती हैं। पूंजीपतियों के मनी पॉवर, मीडिया पॉवर, मसल पॉवर और ब्यूरोक्रेटिक पॉवर कभी इस पार्टी को तो कभी उस पार्टी को सत्ता में बैठाते हैं। इन पूंजीपतियों ने सत्ता हस्तांतरण के बाद इस तरह से शोषण और लूट चलाने के लिए ही आजादी आंदोलन में साजिश रचकर नेताजी सरीखे क्रांतिकारियों को नेतृत्व में टिकने नहीं दिया।

दूसरी तरफ शोषित जनता के अंदर संचित क्षोभ बड़े जन आंदोलन में फूट न पड़ें, इसके लिए भाजपा और आरएसएस एक भयंकर योजना लागू कर रहे हैं। एक दिन राममोहन, विद्यासागर, फूले, रवीन्द्रनाथ, शरत्चन्द्र, प्रेमचंद, सुब्रमणियम भारती, नजरूल आदि लोगों ने मध्ययुगीन धार्मिक कूपमंडुकता को खत्म कर आधुनिक तार्किक, वैज्ञानिक मानसिकता के निर्माण के लिए नवजागरण की मशाल जलायी थी, आज उसी देश को गीता, मनु संहिता, रामायण, महाभारत के धार्मिक अधेरे में डूबोया जा रहा है। अंधविश्वास पैदा किया जा रहा है ताकि जनता जीवन के संकटों के लिए पूंजीवाद और सरकार को जिम्मेदार न ठहराकर उसे अपने 'भाग्य का लिखा', 'पिछले जन्मों का फल', 'विधि का विधान' समझे। तब विरोध और आंदोलन नहीं होंगे। आधुनिक विज्ञान के संपर्क में आकर वैज्ञानिक मानसिकता का निर्माण न हो जाय, इसके लिए प्राचीन भारतीय हिन्दू परम्परा को जगाने के मकसद से हास्यास्पद दावा किया जा रहा है कि गैलिलिओ, न्यूटन, आइंसटीन, हाइजेनबर्ग, आचार्य जगदीश चन्द्र बसु आदि ने कोई आविष्कार नहीं किया। सब कुछ हजारों साल पहले के भारतीय ऋषि-मुनियों के शास्त्रों में लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री ने तो यहां तक दावा कर दिया कि गणेश की मूर्ति ही साबित करती है कि प्राचीन काल में इस देश में प्लास्टिक सर्जरी थी। यह सारा कुछ अध्यात्मवाद और तकनीकी विज्ञान का संमिश्रण कर फासीवादी मानसिकता निर्मित करने के बदतरीन मकसद से किया जा रहा है। फासीवादी हिटलर को भी उग्र जर्मन और आर्य सेंटिमेंट जगाने में इतनी कामयाबी नहीं मिली थी। आगे चलकर शायद भाजपा दावा कर बैठे कि आधुनिक उद्योग, संविधान, न्यायपालिका, संसदीय लोकतंत्र इत्यादि सब कुछ प्राचीन भारत में था। इतिहास को भी विकृत किया जा रहा है। पाठ्यक्रमों में तब्दीली लायी जा रही है। यहां याद करना जरूरी है कि फासीवादी हिटलर की पहल पर जर्मनी में यहूदियों पर जब बर्बर हमले हो रहे थे, तो मनीषी रोमां रोलां, आइंस्टीन, बर्नार्ड शा, रवीन्द्रनाथ, शरत्चन्द्र, प्रेमचंद और दुनिया के जनवादपसंद लोग उसका कड़ा विरोध कर रहे थे। उसी दौरान हिटलर का समर्थन करते हुए सरसंघचालक गोलवलकर ने लिखा था, *''अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को कलुष मुक्त करने के लिए जर्मनी ने पूरी दुनिया को हैरत में डालकर सेमेटिक राष्ट्रीयता—यहूदियों को देश से भगा रहा है। राष्ट्रीयता का गर्व यहां अपने सर्वोच्च महिमा के आसन पर स्थापित हुआ है।...इस सीख को हमें हिन्दुस्तान में अपनाने और उससे लाभान्वित होने की जरूरत है।''* (वी ऑर ऑवर नेशनहूड डिफाइंड) इसी तरह से हिन्दुओं के बीच उग्र मुस्लिम विद्वेश पैदा किया जा रहा है। मानो सारे संकटों के लिए पूंजीवाद नहीं, मुसलमान ही जिम्मेदार हैं। इस तरह से हिन्दू वोट बैंक भी तैयार किया जा रहा है। फिर मुसलमानों के बीच भी हिन्दुओं के बारे में आतंक पैदा किया जा रहा है, 'जीने के लिए मुसलमानों की एकता चाहिए'। इस तरह से स्वार्थी तत्व मुस्लिम वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। जनता के एकताबद्ध संघर्ष को ध्वस्त करने के लिए इस तरह से साम्प्रदायिकता और दंगे की आग भड़कायी जा रही है। जैसा कि 1942 में अगस्त विद्रोह, बाद में आजाद हिन्द फौज का संघर्ष और बम्बे के नौ सेना विद्रोह से पूरे देश में क्रांति की भावनाएं हिलोरे ले रही थीं, तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद और भारतीय पूंजीवाद ने साजिश रचकर 1946 में साम्प्रदायिक दंगा भड़का दिया, क्रांतिकारी आंदोलन की संभावना को रोक दिया और देश का विभाजन हो गया। हिन्दुओं को सोचना होगा कि चैतन्य-रामकृष्ण- विवेकानन्द ने क्या कभी मुस्लिम विद्वेष पैदा किया था, क्या कभी बाबरी मस्जिद ढाहने का आह्वान किया था? वरन् चैतन्य ने हिन्दू-मुसलमानों—सभी के बीच प्रेम का संदेश दिया था। रामकृष्ण ने कहा था, 'जितने मत, उतने पथ'। उन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ी थी, गिरजाघर में प्रार्थना की थी। विवेकानन्द ने वेद-बाइबिल-कुरान का समन्वय कर धार्मिक एकता कायम करने का आह्वान किया था। वे कृष्ण और मुहम्मद का समान रूप से आदर करते थे। उन्होंने यहां तक कहा था, *''...इसलिए यह नितांत स्वाभाविक है कि एक ही साथ पूरी तरह से स्वतंत्र और निर्बिघ्न रूप से मेरा बेटा बौद्ध, मेरी पत्नी ईसाई और मैं स्वयं मुसलमान हो सकता हूं। ...भारत में मुस्लिम विजय ने अत्याचार से पीड़ित लोगों को मुक्ति का स्वाद चखाया था। यही वजह है कि इस देश के पांच में से एक व्यक्ति मुसलमान बन गया था। यह सिर्फ हथियारों के बल पर नहीं हुआ। हथियारों के बल पर और बर्बादी के जरिये यह काम हुआ, ऐसी सोच पागलपन के सिवा कुछ नहीं है। वे जमींदारों और पंडितों के कब्जे से मुक्ति चाहते थे।''* (वाणी और रचना) क्या ये लोग सही हिन्दू थे या ये आरएसएस, भाजपा के नेता हिन्दू हैं? हजरत मुहम्मद ने भी दूसरे धर्मों के प्रति विद्वेष नहीं फैलाया, वरन् उन्होंने अपने पूर्ववर्ती दूसरे धर्म प्रचारकों—इब्राहिम, मुसा और ईशा के बारे में मुसलमानों से कहा था कि वे उन्हें उनके जैसे ही अल्लाह द्वारा भेजे गये पैगम्बर मानें। उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म इस्लाम का मतलब ही होता है शांति। युद्ध और मार-काट में फंसे अरब के बेदुइनों के बीच शांति स्थापित करने के लिए ही उन्होंने ऐसा नाम दिया था। वे विभिन्न धर्मों का सहअस्तित्व चाहते थे। उन्होंने कहा था, 'तुम्हारा अपना धर्म है, मेरा अपना धर्म है'। हम मार्क्सवादी निरीश्वरवादी तो हैं, लेकिन विभिन्न धर्म प्रचारकों के शुरूआती जमाने के ऐतिहासिक और मानव कल्याणकारी भूमिका को आदर की दृष्टि से देखते हैं। और ये सभी हिन्दू और मुसलमान धार्मिक कट्टरपंथी नीच स्वार्थ में धर्म को कलुषित कर रहे हैं। यहां तक कि धर्म के नाम पर दंगा फैला रहे हैं, आतंकी हमले करवा रहे हैं, महिलाओं-बच्चों का कत्लेआम करवा रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार करवा रहे हैं। लोगों को इसके बारे में सचेत रहने की जरूरत है।

सिर्फ शोषण-उत्पीड़न और साम्प्रदायिकता की आग ही नहीं फैलायी जा रही है, शासक वर्ग एक और साजिश में लिप्त है। इस संबंध में 1974 में कॉमरेड शिवदास घोष ने चेतावनी देते हुए कहा था, *''...भारत का शासक वर्ग राष्ट्र के इस नैतिक चरित्र को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश में लगा हुआ है। ...वे जानते हैं कि हजार अत्याचार, दमन, उत्पीड़न चलाकर भुखा रखकर भी किसी राष्ट्र को, किसी देश की जनता को महज पुलिस-फौज की ताकत से ज्यादा दिनों तक दबाकर रखा नहीं जा सकता है।''...जनशक्ति सर ऊंचाकर उठ खड़ी होगी ही, यदि उसे सही क्रांतिकारी विचार प्राप्त हो जाये और उसका नैतिक बल अटूट हो।''* (श्रमिक आंदोलन में क्रांतिकारी दृष्टिकोण क्या हो) बुर्जुआ वर्ग और शासक पार्टियों की साजिश है कि पुराने जमाने के मनीषियों, सुभाषचन्द्र बोस सहित तमाम क्रांतिकारियों व शहीदों की यादों को मिटा डालो, शराबखोरी-जुआखोरी-सट्टबाजी और ब्लू फिल्मों-गंदे यौन साहित्यों की दलदल में छात्र-नौजवानों को धकेल दो ताकि वे इंसान नहीं, पशु नहीं, इंसानियत विहीन मानवदेही जीव बन जायें। इसलिए अपहरण, रेप, गैंगरेप और हत्या रोजमर्रे की घटनाएं बनती जा रही हैं। इस मामले में बच्चियों और प्रौढ़ महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। यही वजह है कि आज सिर्फ अत्यंत गरीबी की तस्वीर ही नहीं दिख रही है, सड़कों पर दिन-रात हमलों की शिकार महिलाओं की चीख-पुकार और मदहोश उन्मादियों का वहशी उल्लास भी सुनाई दे रहा है। क्या देश की इस भयावह गंदगीभरी तस्वीर के बारे में कभी स्वतंत्रता सेनानियों ने सपने में भी सोचा होगा?

देश की इस विकट परिस्थिति में नेताजी के प्रति सही श्रद्धांजली हमें क्या करने को कहती है? नेताजी ने कहा था, *''बचपन में अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ना ही मैं अपना परम कर्त्तव्य समझता था। बाद में गंभीरता से सोचने पर मैंने समझा कि अंग्रेजों को भगा देने से ही हमारे कर्त्तव्यों की इतिश्री नहीं हो जाती। एक नयी सामाजिक व्यवस्था कायम करने के लिए हिन्दुस्तान में एक और क्रांति की जरूरत है।''* (क्रांति क्या है?) इस नई सामाजिक व्यवस्था को लागू करने के लिए पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति की जरूरत है। साथ ही जरूरत है इस युग के श्रेष्ठ क्रांतिकारी विचार मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष विचार से अनुप्राणित हजारों खुदीराम, भगत सिंह, सूर्य सेन, चन्द्रशेखर आजाद, अशफाकउल्ला खान, प्रीतिलता की—जो जनता को सचेत, संगठित और नैतिक बल से बलिष्ठ बनाकर क्रांतिकारी संघर्ष में शामिल करवायेंगे। इस काम में लगना ही है महान क्रांतिकारी योद्धा नेताजी के प्रति सही श्रद्धांजली। छात्र-युवाओं को आज याद करने की जरूरत है आजादी आंदोलन के महान क्रांतिकारी नेता नेताजी की वह अमूल्य सीख, जिसमें वे कहते हैं, *''जुल्म होते देखकर भी जो व्यक्ति उसके खात्मे के लिए कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ अपनी इंसानियत का ही नहीं, बल्कि सताये गये आदमी की इंसानियत का भी अपमान करता है। अन्याय-अत्याचार को खत्म करने की कोशिश में जो व्यक्ति घायल होता है, जेल जाता है अथवा अपमानित होता है, वह उस त्याग और तिरस्कार के जरिये इंसानियत के गौरवशाली आसन को प्राप्त करता है। ...स्कूल-कॉलेजों में, सड़कों पर, मैदानों में, घर-बाहर, जहां भी अन्याय, जुल्म-अत्याचार होते देखो, वहीं वीरों की भांति आगे बढ़कर उसका विरोध करो। ... यदि मैंने अपनी इस छोटी-सी जिन्दगी में कुछ ताकत हासिल की है, तो वह बस इसी रास्ते।''* (तरुणाई के सपने) साथ ही याद करना होगा इस युग की सर्वहारा क्रांति के पथप्रदर्शक कॉमरेड शिवदास घोष के उदात्त आह्वान को, *''जो शुरूआत में ही विचारधारा और आदर्श के लिए कुर्बानियां दे सकते हैं, वे बहुत नहीं, चंद लोग ही होते हैं—यौवन से भरपूर, तेजस्वी, छात्र और नौजवान। हर देश में, समाज विकास के हर स्तर पर ये छात्र और नौजवान ही हैं, जो क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित और लैस होकर आगे आते हैं और पूरी तरह समर्पित होकर जनता के बीच जाते हैं, उन्हें जागृत करते हैं, हजारों की तादाद में संगठित करते हैं और उनकी राजनैतिक शक्ति की सृष्टि करने में सहायक होते हैं। तब एक दिन वक्त आता है जनता द्वारा कार्रवाई करने का, जिसे हम क्रांति कहते हैं।''* (छात्रों और नौजवानों का फर्ज)

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at IPMBC on 7-8 and 22-23 Fortnightly, Date of Printing : 20 June, 2015

कर्नाटक आशा कर्मियों की ऐतिहासिक जीत

कर्नाटक की 30,000 आशा (एक्क्रेडिटिड सोशल हैल्थ एक्टिविस्ट्स) वर्कर 1 मई से अनिश्चितकाल के लिए काम बंद हड़ताल पर चली गई थी। उनकी मांग थी : 1) एक साल से भी ज्यादा समय से बकाया राज्य सरकार का मैचिंग ग्रांट तुरंत जारी की जाये; 2) केन्द्रीय सरकार प्रोत्साहन राशि के बकाया का भुगतान करे; 3) आशा वर्करों के खातों में सीधे ऑन लाइन मासिक पेमेण्ट की जाये; 4) मानदेय/प्रोत्साहन राशि की बजाय न्यूनतम वेतन दिया जाये, आदि।

हड़ताल के 11वें दिन कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री श्री यू टी खादेर ने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों और एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध ''कर्नाटक स्टेट संयुक्त आशा वर्कर्स यूनियन'' के नेताओं की मीटिंग बुलायी। सरकार ने आश्वासन दिया कि मांग पत्र में दी गई सभी 11 मांगों पर समयबद्ध ठोस कदम उठाये जाएंगे। इसके अलावा, काम बंद हड़ताल के दबाव के आगे झुकते हुए राज्य सरकार ने हड़ताल के दौरान राज्य सरकार की ओर से दिये जाने वाले मैचिंग ग्रांट की बकाया राशि का एक हिस्सा पहले ही जारी कर दिया है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद हड़ताल वापस ले ली गई और आशा वर्कर 12 मई से खुशी-खुशी काम पर चली गई। यूनियन ने कष्टों से हासिल हुई इस जीत के लिए न केवल सभी आशा वर्करों को बधाई दी है, बल्कि हड़ताल के दौरान वर्करों का साथ देने वाले ग्रामीणों को भी धन्यवाद दिया है।

सेवा कर वृद्धि के विरोध में एसयूसीआई(सी)

एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 2 जून को जारी एक बयान में कहा :

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने सत्ता में आने का एक साल पूरा होने का समारोह मनाते हुए डींग मारते हुए दावा कर रहे हैं कि देश में 'अच्छे दिन' आ गये हैं, इसी बीच सेवा कर बढ़ाने के जरिये देश की जनता पर एक और जानलेवा हमला बोल दिया है। 1 जून से आम आदमियों को लगभग सभी सेवाओं के इस्तेमाल के लिए 14 प्रतिशत की दर से यह बढ़ा हुआ कर देना होगा। जरूरी सेवाओं के लिए भी टैक्स की यह बढ़ी हुई दर लागू होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जल्द ही 2 प्रतिशत तथाकथित 'स्वच्छ भारत' टैक्स का बोझ इसके साथ जुड़ने जा रहा है। इसके नतीजतन सेवा कर का बोझ होने जा रहा है 16 प्रतिशत। इसके नतीजतन आम आदमियों को और भी ज्यादा निचोड़ा जाएगा। दूसरी तरफ बजट में कारपोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत कर देने के जरिये बड़े-बड़े उद्योगपतियों और कारपोरेट घरानों को 2 लाख करोड़ रुपये की टैक्स छूट मिली थी। यह साफ जाहिर है कि मोदी और उनकी बीजेपी सरकार किसकी बलि देकर किसके लिए 'अच्छे दिन' लाना चाह रही है। यह आखिरी हमला नहीं है, बल्कि उस घोर आर्थिक बर्बरता का पूर्वाभास है जो अपने आकाओं, शासक एकाधिकारी पूंजीपतियों के घृणित वर्ग स्वार्थ की खुली ताबेदारी में बीजेपी आम आदमियों पर ताबड़तोड़ ढाहने पर आमादा है।

आम आदमी से हमारी अपील है कि हमले के आगे झुक कर यह बोझ वहन न करें, बल्कि उठ खड़े होकर संयुक्त रूप से प्रतिवाद करें। इस आर्थिक हमले का मुकाबला करने के लिए देश भर में जोरदार आन्दोलन में बढ़ चढ़ कर शामिल हों।

बीजेपी सांसद आदित्यनाथ के बयान की एआईडीएसओ ने की कड़ी निन्दा

'सूर्य नमस्कार' के मुद्दे पर बीजेपी सांसद आदित्यनाथ द्वारा दिये गये बयान की कड़ी निन्दा करते हुए एआईडीएसओ के महासचिव कॉ. अशोक मिश्रा ने 13 जून को जारी एक बयान में कहा :

गोरखपुर से बीजेपी सांसद आदित्यनाथ के 'सूर्य नमस्कार' को लेकर दिये गये इस बयान की एआईडीएसओ ने कड़ी निन्दा की कि 'जो सूर्य नमस्कार का विरोध करते हैं उन्हें समुद्र में डूब जाना चाहिए'। यह बयान न केवल साम्प्रदायिक व आक्रामक है, बल्कि ऐसी टिप्पणी है जो फासिस्टों को फबती है। यह कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसी टिप्पणी की हो। लेकिन बीजेपी, आरएसएस, शिवसेना, बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं और विचारकों के खिलाफ कोई कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाही नहीं की गई है। यह दर्शाता है कि नरेन्द्र मोदी की वर्तमान बीजेपी-नीत केन्द्र सरकार ने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है जो ऐसे धृष्टतापूर्ण बयान देने के लिए बीजेपी-संघ परिवार को प्रोत्साहित करती है।

यह सच है कि शारीरिक व्यायाम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को ठीक रखने में मदद करता है। प्राचीन भारत में यह एक स्वस्थ परिपाटी थी। पुराने जमाने में ऐसे ही दस्तूर और कौशल दूसरे देशों में भी थे। लेकिन इन अभ्यासों को तत्कालीन परिस्थियों में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जोड़ दिया गया था और रीति-रिवाज सा बना दिया गया था। आधुनिक विज्ञान के आने से मानव शरीर के बारे में हमारा ज्ञान न केवल बढ़ा, बल्कि वैज्ञानिक भी बना। शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में कई गलत धारणाओं को नकार दिया गया और सही समझ हासिल हुई। अब इसका किसी धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए, अगर हम पहले के जमाने में पड़े रहें और मानव शरीर के बारे में वैज्ञानिक सच को न मानें तो इससे हमारी कोई मदद नहीं हो सकती और यह वांछित परिणाम की ओर नहीं ले जा सकता।

यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि 'योग' (शारीरिक व्यायाम करना) और 'योग साधना' (ध्यान लगाना) एक बात नहीं हैं; इन दोनों को गड्डमड्ड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, यह भी है कि शारीरिक व्यायाम मानव देह के बारे में आधुनिक वैज्ञानिक समझ के आधार पर किया जाना चाहिए।

छात्र-शिक्षक-शिक्षाप्रेमी लोगों के आन्दोलन के आगे झुकी हरियाणा राज्य सरकार

राज्य के सभी शिक्षाप्रेमी लोगों को शामिल कराते हुए ऑल इण्डिया डीएसओ द्वारा शुरू किये गये शक्तिशाली आन्दोलन के दबाव में हरियाणा सरकार ने स्कूलों में सेमेस्टर प्रणाली वापस लेने का फैसला लिया है जो इसने स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक पहले चालू की थी। इस दोषपूर्ण सेमेस्टर प्रणाली के खिलाफ इस जीत से शिक्षा से सरोकार रखने वाले तमाम तबकों के बीच उत्साह की लहर पैदा हो गई है। इसने दिखा दिया है कि एकताबद्ध होकर जोरदार आन्दोलन विकसित करने के जरिये ही लोग अपनी जायज मांगों को मनवा सकते हैं।

आंगनवाड़ी कर्मियों व अन्य कर्मचारियों ने की रैली और बड़े आन्दोलन का संकल्प लिया

करनाल में सी एम कैम्प आफिस का घेराव करने जा रही आंगनवाड़ी कर्मियों व अन्य कर्मचारियों को बैरिकेड लगाकर पुलिस ने रोका

करनाल (हरियाणा) : ज्वाइंट प्लेटफार्म ऑफ एक्शन (जेपीए), संयुक्त कर्मचारी मंच, आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हैल्पर्स यूनियन सहित विभिन्न कर्मचारी यूनियनों की ओर से 6 जून को अपनी विभिन्न लम्बित मांगों को लेकर कर्ण पार्क, करनाल में एक रैली की गई। इसमें पानीपत, रोहतक, करनाल, कैथल, रेवाड़ी, हिसार, गुड़गांव, झज्जर आदि कई जिलों से आंगनवाड़ी कर्मी और अन्य कर्मचारी शामिल हुए। इसके बाद वे मुख्यमंत्री के कैम्प कार्यालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़े लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही उनको रोक दिया। उन्होंने एसडीएम को अपना ज्ञापन सौंपा जिन्होंने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

रैली ने 30 जून तक इन्तजार करने का ऐलान किया। अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो और भी बड़े स्तर पर आन्दोलन किया जाएगा।

"Print-line
Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."
Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com फोन नं. : 011-25726631